भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1007

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

नक्सल प्रभावित जिलों में विकास संबंधी योजनाएं

†1007. श्री हरिवंश :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नक्सल प्रभावित जिलों में विकास की कौन-कौन सी योजनाएं चलायी जा रही हैं;

(ख) बिहार और झारखण्ड के नक्सल प्रभावित जिलों में केन्द्र सरकार की ओर से कितनी राशि अब तक दी गयी है; और

(ग) कितनी योजनाएं शुरु हो चुकी हैं, तथा कितनी योजनाएं पाइपलाईन में हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) से (ग) : वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए नीति आयोग द्वारा क्रियान्वित की जा रही अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही सड़क आवश्यकता योजना (आरआरपी-I) नामक दो प्रमुख विकास संबंधी योजनाएं हैं जिनके तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, जिसके तहत लोक अवसंरचना और सेवाओं के सृजन पर ध्यान दिया जा रहा है, पूर्व में वर्ष 2010-11 से एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) के रूप में कार्यान्वयन की जा रही थी। वारहवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना के रूप में एकीकृत कार्य योजना को जारी रखने के संबंध में सरकार द्वारा दिनांक 01.08.2013 को अनुमोदन प्रदान किया गया था। प्रारंभ में, इस योजना के दायरे में 60 जिले शामिल थे जबकि अब इसके तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 76 जिलों सहित 88 जिले शामिल हैं (आंध्र प्रदेश-04, बिहार-11, छत्तीसगढ़-14, झारखंड-17, मध्य प्रदेश-10, महाराष्ट्र-04, ओडिशा-18, तेलंगाना-04, उत्तर प्रदेश-03 और पश्चिम बंगाल-03)। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष प्रति जिला निधि आबंटन वर्ष 2010-11 में 25.00 करोड़ रु. तथा बाद के वर्षों में 30.00 करोड़ रु. था। योजना के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों में 1,60,908 परियोजनाएं चलाई गईं जिनमें से 26.02.2015 की स्थिति के अनुसार 1,29,037 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं तथा जारी की गईं 9,059.00 करोड़ रु. की कुल केन्द्रीय निधियों की तुलना में 8149.16 करोड़ रु. के व्यय होने की सूचना प्राप्त हुई है। बिहार और झारखंड को क्रमश: 1013.38 करोड़ रु. तथा 1894.19 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता राशि जारी की गई है।

.....2/-

08 राज्यों के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों (तेलंगाना-01, बिहार-06, छत्तीसगढ़-07, झारखंड-11, मध्य प्रदेश-01, महाराष्ट्र-02, ओडिशा-05 और उत्तर प्रदेश-01), में वर्ष 2009-10 से क्रियान्वित की जा रही सड़क आवश्यकता योजना-। में 7,300.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 5,477 कि.मी. सड़कों का विकास परिकल्पित है। स्वीकृत कुल 5,469 कि.मी. लम्बाई में से 31.01.2015 की स्थिति के अनुसार 4,511.00 करोड़ रु. के व्यय से 3,387 किमी लम्बाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2014-15 तक बिहार और झारखंड को क्रमश: 656 करोड़ रु. तथा 805 करोड़ रु. की निधियां आबंटित की गई हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा क्रमश: 'रोशनी' और 'कौशल विकास' नामक 02 कौशल विकास संबंधी योजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही हैं।

रोशनी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (पूर्ववर्ती आजीविका कौशल) के अंतर्गत एक विशेष पहल है जो 09 राज्यों के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 27 जिलों (आंध्र प्रदेश-01, बिहार-02, छत्तीसगढ़-08, झारखंड-06, मध्य प्रदेश-01, महाराष्ट्र-01, ओडिशा-06, उत्तर प्रदेश-01 और पश्चिम बंगाल-01) में निर्धन ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण और रोजगार हेतु जून, 2013 में आरंभ की गई थी। अब तक 16.82 करोड़ रु. की कुल लागत से बिहार में 1085 अभ्यर्थियों को कौशल प्रदान करने के लिए दो रोशनी परियोजनाएं तथा 100.96 करोड़ रु. की कुल लागत से झारखंड में 3956 अभ्यर्थियों को कौशल प्रदान करने के लिए आठ रोशनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

वर्ष 2011-12 से क्रियान्वित की जा रही वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में 'कौशल विकास' नामक योजना का मुख्य लक्ष्य 09 राज्यों के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों (तेलंगाना-01, बिहार-06, छत्तीसगढ़-07, झारखंड-10, मध्य प्रदेश-01, महाराष्ट्र-02, ओडिशा-05, उत्तर प्रदेश-01 तथा पश्चिम बंगाल-01) में प्रत्येक जिले में 01 आईटीआई तथा 02 कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना करना तथा दीर्घ कालिक प्रशिक्षण तथा अल्पकालिक प्रशिक्षण और अनुदेशक प्रशिक्षण पाठयक्रमों को शामिल करते हुए मांग आधारित व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करना है। बिहार और झारखंड को क्रमश: 41.69 करोड़ रु तथा 69.48 करोड़ रु. की धनराशि आबंटित की गई है।

इसके अतिरिक्त, दूर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में यूनिवर्सल सर्विस आब्लीगेशन फंड (यूएसओएफ) समर्थित मोबाइल सेवा योजना कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना बीएसएनएल द्वारा पहले से प्रतिष्ठापित 363 स्थानों (आंध्र प्रदेश-01, छत्तीसगढ़-351, महाराष्ट्र-03, मध्य प्रदेश-06 और तेलंगाना-02) सहित 2199 स्थानों (आंध्र प्रदेश-41, बिहार-184, छत्तीसगढ़-497, झारखंड-782, महाराष्ट्र-60, मध्य प्रदेश-22, आडिशा-253, तेलंगाना-186, उत्तर प्रदेश-78 और पश्चिम बंगाल 96) में मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा 20.08.2014 को अनुमोदित की गई थी। परियोजना की अनुमानित कार्यान्वयन लागत 3567.58 करोड़ रु. है। इस योजना के अंतर्गत बीएसएनएल को 596.51 करोड़ रु. की राशि संवितरित की गई है।

****